



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 2012/आषाढ 1, 1934

No. 297]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 2012/ASADHA I, 1934

गृह मंत्रालय

(सी एस प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2012

सा.का.नि. 493(अ).— बन्दी प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के प्रावधान मालदीव गणराज्य की सरकार पर प्रयोज्य होंगे तथा उस देश तथा भारत के बीच बंदियों के अन्तरण के लिए भारत सरकार एवं मालदीव गणराज्य के बीच हुए करार के पाठ को अधिसूचित करती है। नामतः -

दण्डित व्यक्तियों के अन्तरण के संबंध में भारत गणराज्य तथा मालदीव गणराज्य के बीच करार

भारत गणराज्य तथा मालदीव गणराज्य, जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकार देश कहा गया है;

दण्डित व्यक्तियों का उनके स्वयं के देशों में सामाजिक पुनर्वास सुगम बनाने की अभिलाषा से;
और

यह मानते हुए कि यह उद्देश्य, कोई दंडिक अपराध करने के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध और दंडित किए गए विदेशी नागरिकों को उनके स्वयं के समाज में अपनी सजा काटने का अवसर प्रदान करके पूरा किया जाना चाहिए;

निम्न प्रकार सहमत हो गई हैं :

अनुच्छेद 1

परिभाषा

इस करार के प्रयोजन के लिए :

- (क) "निर्णय" से तात्पर्य न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के किसी ऐसे निर्णय अथवा आदेश से है जिसके तहत दण्ड दिया गया हो;
- (ख) "प्राप्तकर्ता देश" से तात्पर्य उस देश से है जिसको दण्डित व्यक्ति सजा अथवा बाकी की सजा काटने के प्रयोजन से अंतरित किया जा सकता हो अथवा अंतरित किया गया हो;
- (ग) "दण्ड" से तात्पर्य अपने दंडिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया कोई ऐसा अंतिम दंड या उपाय है जिसमें निर्धारित समयावधि के लिए आजादी से वंचित रखा जाना या आजीवन कारावास शामिल हो;
- (घ) "दण्डित व्यक्ति" से तात्पर्य किसी दंडिक न्यायालय, जिसमें संविदाकार देश में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा स्थापित न्यायालय भी शामिल हैं, द्वारा पारित किसी आदेश के तहत कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति से है;
- (ङ) "अंतरणकर्ता देश" से तात्पर्य उस देश से है जिसमें उस व्यक्ति को दंड दिया गया हो, जिसे अंतरित किया जा सकता हो या जिसे अंतरित कर दिया गया हो।

अनुच्छेद 2

सामान्य सिद्धांत

1. किसी संविदाकार देश के भू-भाग में दंडित किसी व्यक्ति को इस करार के प्रावधानों के अनुसार दूसरे संविदाकार देश के भू-भाग में अंतरित किया जा सकता है ताकि वह उसे दी गई

सजा काट सके। इस संबंध में दंडित व्यक्ति अन्तरणकर्ता देश अथवा प्राप्तकर्ता देश से इस करार के अंतर्गत ऐसे अंतरण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है।

2. अन्तरण का अनुरोध किसी दंडित व्यक्ति द्वारा, जो किसी संविदाकार देश का नागरिक है, अथवा संविदाकार देश के कानूनों के अनुसार उसके स्थान पर कार्य करने के हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा संविदाकार देश को और उक्त संविदाकार देश के कानूनों द्वारा निर्धारित किए गए तरीके से आवेदन प्रस्तुत करके किया जा सकता है।

अनुच्छेद 3

केन्द्रीय प्राधिकारी

1. संविदाकार देशों की ओर से इस करार के कार्यान्वयन के बारे में प्रभारी प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:

भारत गणराज्य के लिए : गृह मंत्रालय

मालदीव गणराज्य के लिए : मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स

2. यदि कोई संविदाकार देश अपना सक्षम प्राधिकारी बदलता है तो वह दूसरे देश को सरकारी चैनलों के माध्यम से उक्त परिवर्तन के बारे में अधिसूचित करेगा।

अनुच्छेद 4

अंतरण की शर्तें

इस करार के अंतर्गत किसी दंडित व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर ही अन्तरित किया जा सकता है :

(क) वह व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का नागरिक हो;

- (ख) दंडित व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दिया गया हो;
- (ग) निर्णय अंतिम हो;
- (घ) अन्तरणकर्ता देश में दंडित व्यक्ति के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही, जिसमें उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो, लम्बित नहीं हो;
- (ङ) दंडित व्यक्ति को सैन्य कानून के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया हो;
- (च) अंतरण के अनुरोध की प्राप्ति के समय, दंडित व्यक्ति द्वारा भोगी जाने वाली सजा की अवधि कम से कम छः माह बची हो;
- (छ) कि व्यक्ति को अंतरणकर्ता देश में जिन कृत्यों अथवा चूकों के लिए दंड दिया गया था, वे प्राप्तकर्ता देश में दंडनीय अपराध हैं, अथवा यदि उसके अपने भू-भाग में किए जाते तो दाण्डिक अपराध होते;
- (ज) प्राप्तकर्ता देश में दंडित व्यक्ति की हिरासत को अंतरित करने से अंतरणकर्ता देश की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा किसी अन्य हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो;
- (झ) यदि अंतरण के संबंध में दंडित व्यक्ति अथवा दंडित व्यक्ति की आयु अथवा शारीरिक या मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर, किसी भी संविदाकार देश द्वारा जरूरी समझे जाने पर, संविदाकार देश के कानून के अनुसार उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहमति दी गई हो; और
- (ञ) अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हों।

2. आपवादिक मामलों में, यदि दंडित व्यक्ति द्वारा भोगे जा रहे दंड की शेष अवधि छः माह से कम हो तो भी अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद 5

सूचना भेजने का दायित्व

- यदि दंडित व्यक्ति ने अंतरणकर्ता देश को इस करार के तहत अन्तरित होने की इच्छा व्यक्त की हो तो, अंतरणकर्ता देश प्राप्तकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना तथा दस्तावेज भेजेगा

बशर्ते कि प्राप्तकर्ता या अन्तरणकर्ता देश में से किसी के भी द्वारा पहले ही ऐसा कोई निर्णय न लिया गया हो कि वह अन्तरण के लिए सहमत नहीं है :

(क) दंडित व्यक्ति का नाम और राष्ट्रीयता, जन्म तिथि एवं जन्म स्थान तथा प्राप्तकर्ता देश में उसका पता, यदि कोई हो, उसके पासपोर्ट अथवा कोई अन्य व्यक्तिगत पहचान संबंधी दस्तावेजों की प्रति तथा यथासंभव दंडित व्यक्ति के अंगुलिछाप;

(ख) उन तथ्यों का विवरण जिन पर दंड आधारित था;

(ग) दंड की प्रकृति, समयावधि एवं प्रारंभ होने की तारीख;

(घ) निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा कानून के उन संगत उपबंधों की एक प्रति जिनके अंतर्गत दंडित व्यक्ति के खिलाफ दंड पारित किया गया है;

(ङ) दंडित व्यक्ति की कोई चिकित्सीय, सामाजिक अथवा पूर्ववृत्तों एवं चरित्र के बारे में कोई अन्य रिपोर्ट, जहां वह उसके आवेदन के निपटान अथवा उसकी परिरुद्धता की प्रकृति के निर्धारण के लिए प्रासंगिक हो;

(च) कोई अन्य जानकारी जिसे अन्तरणकर्ता देश विनिर्दिष्ट करे कि यह अंतरण की संभावना पर विचार करने और अपने कानून के अंतर्गत दंडित व्यक्ति को अंतरण के सम्पूर्ण परिणामों की जानकारी देने में सक्षम होने के लिए जरूरी है;

(छ) अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्ति अथवा अंतरणकर्ता देश के कानून के अनुसार उसकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति अथवा दंडित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि का अनुरोध;

(ज) किसी विचारण-पूर्व नजरबंदी, क्षमा या दंड प्रवर्तन के लिए संगत किसी अन्य तथ्य को शामिल करते हुए, एक विवरण जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कितना दंड पूरा हो चुका है; और

(झ) दंडित व्यक्तियों के अन्तरण पर सहमति देते हुए अन्तरणकर्ता देश की ओर से एक विवरण।

2. इस करार के अधीन किसी अनुरोध पर कोई भी निर्णय लिए जाने के प्रयोजन के लिए प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज तभी भेजेगा जब

2251/97/12-2

प्राप्तकर्ता या अंतरणकर्ता देश ने पहले ही यह निश्चय कर लिया हो कि वह अंतरण से सहमत नहीं है :

(क) एक विवरण अथवा दस्तावेज जो यह दर्शाता हो कि दण्डित व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का एक नागरिक है;

(ख) प्राप्तकर्ता देश के संगत कानून की एक प्रति जिसमें यह प्रावधान किया गया हो कि ऐसे कृत्य अथवा चूकें, जिनके कारण अंतरणकर्ता देश में दण्ड पारित किया गया है, प्राप्तकर्ता देश के कानून के अंतर्गत दण्डिक अपराध माने गए हैं अथवा यदि, इसके भू-भाग में घटित होते तो दण्डिक अपराध माने जाते;

(ग) दण्डित व्यक्ति के अन्तरण पर इस करार के अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 2 के प्रभाव के विवरण, यदि लागू हो, सहित उसके अन्तरण के बाद प्राप्तकर्ता देश में सजा की अवधि एवं प्रवर्तन संबंधी किसी कानून अथवा विनियम के प्रभाव का विवरण;

(घ) दण्डित व्यक्ति के अंतरण को स्वीकार करने के लिए प्राप्तकर्ता देश की सहमति और दण्डित व्यक्ति की सजा के बाकी बचे हिस्से को शासित करने हेतु एक वचनबद्धता; तथा

(ङ) कोई अन्य सूचना अथवा दस्तावेज जिसे अंतरणकर्ता देश आवश्यक समझे।

अनुच्छेद 6

अनुरोध एवं जवाब

1. अंतरण के लिए अनुरोध निर्धारित प्रपत्र, यदि कोई है, में लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे और राजनयिक चैनलों के माध्यम से अन्तरणकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्तकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकारी को सम्बोधित किए जाएंगे। जवाब उन्हीं चैनलों के माध्यम से सूचित किए जाएंगे।

2. प्राप्तकर्ता देश शीघ्रतापूर्वक अन्तरणकर्ता देश को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा कि वह प्रार्थित अंतरण के लिए सहमत है अथवा नहीं।

अनुच्छेद 7सहमति और इसका सत्यापन

1. अंतरणकर्ता देश यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अनुच्छेद 4 के पैराग्राफ 1 (झ) के अनुसार अंतरण के लिए सहमति देने वाला व्यक्ति, ऐसा स्वेच्छा से तथा इसके कानूनी परिणामों की पूरी जानकारी के साथ कर रहा है। इस प्रकार की सहमति देने की प्रक्रिया को अंतरणकर्ता देश के कानून द्वारा शासित किया जाएगा।
2. अंतरणकर्ता देश, प्राप्तकर्ता देश को यह सत्यापित करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा कि सहमति, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रदान की गई है।

अनुच्छेद 8प्राप्तकर्ता देश के लिए अंतरण का प्रभाव

1. इस करार के अनुच्छेद 9 में निर्धारित शर्तों के अधीन, प्राप्तकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश, जैसा भी इसके राष्ट्रीय कानून के तहत अपेक्षित होगा, के माध्यम से सजा का प्रवर्तन जारी रखेंगे।
2. इस करार के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के अधीन, सजा का प्रवर्तन प्राप्तकर्ता देश के कानून द्वारा शासित किया जाएगा और कि सिर्फ वही देश समस्त समुचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

अनुच्छेद 9सजा का सतत प्रवर्तन

1. प्राप्तकर्ता देश, अंतरणकर्ता देश द्वारा यथा अभिनिर्धारित सजा की विधिक प्रकृति एवं अवधि द्वारा आबद्ध होगा।
2. यदि सजा की प्रकृति अथवा अवधि अथवा दोनों ही, प्राप्तकर्ता देश के कानून से असंगत हों, तो वह देश, अंतरणकर्ता देश की पूर्व सहमति से, सजा को अपने स्वयं के कानून द्वारा उसी प्रकार के अपराध के लिए निर्धारित दण्ड अथवा उपाय में रूपान्तरित कर सकेगा। जहां तक दण्ड

अथवा उपाय की प्रकृति एवं अवधि का संबंध है, अंतरणकर्ता देश के अधिनिर्णय द्वारा आरोपित सजा के अनुरूप होगा। तथापि, यह अपनी प्रकृति अथवा अवधि द्वारा, अंतरणकर्ता देश में आरोपित की गई सजा में वृद्धि नहीं करेगा।

अनुच्छेद 10

अंतरणकर्ता देश के लिए सजा के समापन का प्रभाव

जब प्राप्तकर्ता देश इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 1 (क) के तहत अंतरणकर्ता देश को यह अधिसूचित करता है कि सजा पूरी हो गई है, तो ऐसी अधिसूचना अंतरणकर्ता देश में उस सजा को समाप्त (रिहा) करने में प्रभावी मानी जाएगी।

अनुच्छेद 11

निर्णय की समीक्षा और माफी, राजक्षमा अथवा लघुकरण

(1) केवल अंतरणकर्ता देश को ही निर्णय की पुनरीक्षा के लिए किसी आवेदन-पत्र पर निर्णय लेने का अधिकार होगा।

(2) कोई भी संविदाकार देश अपने संविधान अथवा अन्य कानूनों के अनुरूप दंड की माफी, राजक्षमा प्रदान कर सकेगा अथवा दण्ड का लघुकरण कर सकेगा।

अनुच्छेद 12

दण्ड के प्रवर्तन की समाप्ति

1. अंतरणकर्ता देश अपने भू-भाग में लिए गए किसी भी निर्णय, जिसके द्वारा दंड अथवा इसके किसी हिस्से के प्रवर्तन का समापन अपरिहार्य हो गया हो, के बारे में तत्काल प्राप्तकर्ता देश को अधिसूचित करेगा;

2. जैसे ही अंतरणकर्ता देश द्वारा किसी भी ऐसे फैसले अथवा उपाय की सूचना दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दंड प्रवर्तन योग्य नहीं रह जाता, तो प्राप्तकर्ता देश दंड अथवा दंड के हिस्से के प्रवर्तन को समाप्त कर देगा।

अनुच्छेद 13दण्ड के प्रवर्तन संबंधी सूचना

1. प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को अधिसूचित करेगा :

(क) जब दण्ड का प्रवर्तन पूरा कर लिया गया हो; अथवा

(ख) यदि दण्ड का प्रवर्तन पूरा होने से पहले दंडित व्यक्ति हिरासत से भाग जाता है, ऐसे मामलों में प्राप्तकर्ता देश दंडित व्यक्ति की गिरफ्तारी के उपाय करेगा ताकि वह दंड का शेष भाग पूरा कर सके तथा उसे प्राप्तकर्ता देश के संगत कानून के अन्तर्गत जेल से भागने के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सके।

2. यदि अंतरणकर्ता देश द्वारा अपेक्षित हो, तो प्राप्तकर्ता देश दंड के प्रवर्तन के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद 14अभिवहन

1. यदि कोई भी संविदाकार देश दंडित व्यक्तियों के अंतरण के लिए किसी तीसरे देश के साथ कोई व्यवस्था करता है, तो दूसरा संविदाकार देश ऐसी व्यवस्था के अनुसरण में अपने भू-भाग से अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्तियों के अभिवहन को सुचारु बनाने में सहयोग करेगा, सिवाय इसके कि वह निम्न के कारण अभिवहन से इनकार करे;

(क) यदि, दंडित व्यक्ति वहीं का राष्ट्रिक हो,

(ख) अनुरोध से संविदाकार देश की संप्रभुता, सुरक्षा, लोक-व्यवस्था अथवा अन्य मौलिक हित का अतिक्रमण होता हो।

2. ऐसे अंतरण का इच्छुक संविदाकार देश दूसरे संविदाकार देश को ऐसे अभिवहन के बारे में अग्रिम नोटिस देगा।

अनुच्छेद 15लागत

अंतरणकर्ता देश के अनन्य भू-भाग में होने वाले व्ययों को छोड़कर, इस करार को लागू करने में आने वाले सभी व्यय प्राप्तकर्ता देश द्वारा वहन किए जाएंगे। तथापि, प्राप्तकर्ता देश, अंतरण में

होने वाले सम्पूर्ण अथवा आंशिक व्यय की वसूली दंडित व्यक्ति अथवा किसी अन्य संसाधन से प्राप्त कर सकता है।

अनुच्छेद 16

भाषा

अनुरोध एवं सहायक दस्तावेज अंग्रेजी में होंगे अथवा उनके साथ अंग्रेजी अनुवाद संलग्न होगा।

अनुच्छेद 17

लागू होने का दायरा

यह करार, इसके प्रभावी होने की तारीख से पहले या बाद में लगाए गए दण्ड के प्रवर्तन पर लागू होगा।

अनुच्छेद 18

विवादों का निपटान

1. केन्द्रीय प्राधिकारी इस करार की व्याख्या, लागू होने या कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को परस्पर सहमति से सुलझाने का प्रयास करेंगे।
2. यदि केन्द्रीय प्राधिकारी इस विवाद को परस्पर सहमति से नहीं सुलझा पाते हैं तो इसे राजनयिक चैनलों से सुलझाया जाएगा।

अनुच्छेद 19

दण्डित व्यक्तियों को सौंपना

अंतरित किए जाने वाले व्यक्ति को अन्तरणकर्ता देश द्वारा प्राप्तकर्ता देश को एक ऐसे स्थान पर सौंपा जाएगा जिसके लिए अन्तरणकर्ता तथा प्राप्तकर्ता देश के बीच सहमति हो गई हो। प्राप्तकर्ता देश कैदी के अंतरणकर्ता देश से अभिवहन के लिए जिम्मेवार होगा तथा वह अंतरणकर्ता देश के भू-भाग से बाहर दण्डित व्यक्ति की हिरासत के लिए भी जिम्मेवार होगा।

अनुच्छेद 20संशोधन

संविदाकार देशों द्वारा सहमत इस करार में कोई संशोधन अथवा आशोधन उसी प्रकार से लागू होगा जैसाकि करार लागू है।

अनुच्छेद 21अंतिम प्रावधान

1. यह करार अनुसमर्थन के अध्यधीन होगा। प्रत्येक संविदाकार पक्ष करार के लागू होने के लिए आवश्यक अपनी कानूनी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने पर, राजनयिक चैनलों के माध्यम से, यथा संभव शीघ्र लिखित में दूसरे संविदाकार पक्ष को सूचित करेगा। यह करार अंतिम अधिसूचना की तारीख के बाद दूसरे माह के पहले दिन से प्रभावी होगा।

2. यह करार अनिश्चित काल तक लागू रहेगा। तथापि, यह करार, किसी भी संविदाकार देश द्वारा दूसरे संविदाकार देश को करार के परिसमापन की लिखित सूचना देकर परिसमाप्त किया जा सकेगा। यह परिसमापन ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से छह माह बाद प्रभावी होगा।

3. किसी भी परिसमापन के बावजूद, यह करार उन दंडित व्यक्तियों के दंडों के प्रवर्तन पर लागू रहेगा जिन्हें इस परिसमापन के लागू होने की तारीख से पहले इस करार के अंतर्गत अंतरित किया गया हो।

इस करार के साक्ष्य के रूप में, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा इस संबंध में उचित प्रकार से प्राधिकृत किए जाने पर अधोहस्ताक्षरी ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित होने के नाते इसे में
दिनांक को हिन्दी और अंग्रेजी, में दो प्रतियों में तैयार किया गया है। व्याख्या में मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की

सरकार की ओर से

मालदीव गणराज्य की

सरकार की ओर से

[फा. सं. 17011/08/2009-पी आर]

एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(CS Division)****NOTIFICATION****New Delhi, the 21st June, 2012**

G.S.R. 493(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections(1) and (2) of section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Government of Republic of Maldives and notifies the text of the treaty entered into between the Government of the Republic of India and the Government of Republic of Maldives for the transfer of prisoners between that country and India as follows, namely :-

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MALDIVES ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Maldives hereinafter referred to as the Contracting States;

Desiring to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons into their own countries; and

Considering that this objective should be fulfilled by giving foreign nationals, who have been convicted and sentenced as a result of their commission of a criminal offence, the opportunity to serve their sentences within their own society;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purpose of this Agreement:

- (a) "judgment" means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence;
- (b) "receiving State" means a State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence or remainder thereof;
- (c) "sentence" means any final punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or tribunal for a determinate period of time, or for life imprisonment, in the exercise of its criminal jurisdiction;
- (d) "sentenced person" means a person undergoing a sentence of imprisonment under a judgement passed by a criminal court including the courts established under the law for the time being in force in the Contracting States;
- (e) "transferring State" means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been transferred.

ARTICLE 2

General Principles

1. A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express to the transferring State or the receiving State his willingness to be transferred under this Agreement.

2. Transfer may be requested by any sentenced person who is a national of a Contracting State or by any other person who is entitled to act on his behalf in accordance with the laws of the Contracting State or by making an application to the Contracting State and in the manner prescribed by the laws of the Contracting State.

2251 47/12-4

ARTICLE 3**Central Authorities**

1. Authorities in charge of the implementation of this Agreement for the Contracting States are:

For the Republic of India: the Ministry of Home Affairs;

For the Republic of Maldives: the Ministry of Home Affairs.

2. In case either Contracting State changes its competent authorities, it shall notify the other State of the same through diplomatic channels.

ARTICLE 4**Conditions for transfer**

1- A sentenced person may be transferred under this Agreement only on the following conditions:

- (a) the person is a national of the receiving State;
- (b) the death penalty has not been awarded to the sentenced person;
- (c) the judgment is final;
- (d) no criminal proceedings are pending against the sentenced person in the transferring State in which his presence is required;
- (e) the sentenced person has not been convicted for an offence under the military law;
- (f) at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least six months of the sentence to serve;
- (g) that the acts or omissions for which that person was sentenced in the transferring State are those which are punishable as a crime in the receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
- (h) transfer of custody of the sentenced person to the receiving State shall not be prejudicial to the sovereignty, security or any other interest of the transferring State;
- (i) consent to the transfer if given by the sentenced person or, where in view of his age or physical or mental condition either Contracting State considers it necessary, by any other person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State; and
- (j) the transferring and receiving States agree to the transfer.

2. In exceptional cases, the transferring and receiving States may agree to a transfer even if the remaining period to be served by the sentenced person is less than six months.

ARTICLE 5

Obligation to furnish information

1. If the sentenced person has expressed an interest to the transferring State in being transferred under this Agreement, the transferring State shall send the following information and documents to the receiving state unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:

- (a) the name and nationality, date and place of birth of the sentenced person and his address, if any, in the receiving State along with a copy of his passport or any other personal identification documents, and fingerprints of the sentenced person, as possible;
- (b) a statement of the facts upon which the sentence was based;
- (c) the nature, duration and date of commencement of the sentence;
- (d) a certified copy of the judgment and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the sentenced person;
- (e) a medical, social or any other report regarding the antecedents and character of the sentenced person, where it is relevant for the disposal of his application or for deciding the nature of his confinement;
- (f) any other information which the transferring State may specify as required to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences of transfer for him/her under its law;
- (g) the request of the sentenced person to be transferred or of a person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the transferring State,

- (h) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence, and
- (i) A statement from the Transferring State agreeing to the transfer of the Sentenced Persons.

2. For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the receiving State shall send the following information and documents to the transferring State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:

- (a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the receiving State;
- (b) a copy of the relevant law of the receiving State which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the transferring State constitute a criminal offence according to the law of the receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
- (c) a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the receiving State after the sentenced person's transfer including, if applicable, a statement of the effect of paragraph 2 of Article 9 of this Agreement on his transfer;
- (d) the willingness of the receiving State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of the sentenced person; and
- (e) any other information or document which the transferring State may consider necessary.

ARTICLE 6**Requests and replies**

1. Requests for transfer shall be made in writing in the prescribed proforma, if any, and addressed by the central authority of the transferring State through diplomatic channels to the central authority of the receiving State. Replies shall be communicated through the same channels.
2. The receiving State shall promptly inform the transferring State of its decision whether or not to agree to the requested transfer.

ARTICLE 7**Consent and its verification**

1. The transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with paragraph 1 (i) of Article 4 of this Agreement, does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the transferring State.
2. The transferring State shall afford an opportunity to the receiving State to verify that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

ARTICLE 8**Effect of transfer for the Receiving State**

1. The competent authorities of the receiving State shall continue the enforcement of the sentence through a court or administrative order, as may be required under its national law, under the conditions set out in Article 9 of this Agreement.
2. Subject to the provisions of Article 11 of this Agreement, the enforcement of the sentence shall be governed by the law of the receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.

2251 47/12-5

ARTICLE 9**Continued enforcement of sentence**

1. The receiving State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the transferring State.
2. If the sentence is by its nature or duration, or both, incompatible with the law of the receiving State, that State may, with the prior consent of the transferring State, by court or administrative order, adapt the sentence to a punishment or measure prescribed by its own law. As to its nature and duration the punishment or measure shall, as far as possible, correspond with that imposed by the judgment of the transferring State. It shall however not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed by the transferring State.

ARTICLE 10**Effect of completion of sentence for the transferring State**

When the receiving State notifies the transferring State under paragraph 1(a) of Article 13 of this Agreement that the sentence has been completed, such notification shall have the effect of discharging that sentence in the transferring State.

ARTICLE 11**Review of judgement and Pardon, Amnesty or Commutation of sentence**

1. The transferring State alone shall have the right to decide on any application for the review of the judgement.
2. Either of the Contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its Constitution or other laws.

ARTICLE 12**Termination of enforcement of sentence**

1. The transferring State shall promptly notify the receiving State of any decisions taken in its territory which entails terminating the enforcement of the sentence or part thereof.
2. The receiving State shall terminate enforcement of the sentence or part thereof as soon as it is informed by the transferring State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

ARTICLE 13**Information on enforcement of sentence**

1. The receiving State shall notify the transferring State:
 - (a) when the enforcement of the sentence has been completed; or
 - (b) If the sentenced person escapes from custody before enforcement of the sentence has been completed, in such cases, the receiving State shall take measures to secure his arrest for the purposes of serving the remainder of his sentence and to render him/her liable for committing an offence under the relevant laws of the receiving State.
2. The receiving State shall furnish a special report concerning the enforcement of the sentence, if so required by the transferring State.

ARTICLE 14**Transit**

1. If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with any third State, the other Contracting State shall cooperate in facilitating the transit through its territory of the sentenced persons being transferred pursuant to such arrangements, except that it may refuse to grant transit;
 - (a) if the sentenced person is one of its own nationals,

2251 97/12-6

- (b) if the request may infringe upon the sovereignty, safety, public order or any other essential interest of the Contracting State.

2. The Contracting State intending to make such a transfer shall give advance notice to the other Contracting State of such transit.

ARTICLE 15

Costs

Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the receiving State, except costs incurred exclusively in the territory of the transferring State. The receiving State may, however, demand or seek to recover all or part of the costs of transfer from the sentenced person or from some other source.

ARTICLE 16

Language

Requests and supporting documents shall be in English or shall be accompanied by a translation into English.

ARTICLE 17

Scope of application

This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 18

Settlement of Disputes

- (1) The Central Authorities shall endeavor to mutually resolve any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Agreement.
- (2) If the Central Authorities are unable to resolve the dispute mutually, it shall be resolved through diplomatic channels.

ARTICLE 19
Handing over of sentenced persons

The handing over of the transferred person by the transferring State to the receiving State shall occur at a place to be agreed upon between the transferring and receiving State. The receiving State shall be responsible for the transport of the prisoner from the transferring State and shall also be responsible for custody of the sentenced person outside the territory of the transferring State.

ARTICLE 20
Amendments

Any amendments or modifications to this Agreement agreed to by the Contracting States shall come into force in the same manner as the Agreement itself.

ARTICLE 21
Final provisions

1. This Agreement shall be subject to ratification. Each Contracting State shall notify the other as soon as possible, in writing, through diplomatic channels, upon the completion of its legal procedures required for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall come into force on the first day of the second month of the date of the last notification.
2. The Agreement remain in force for an indefinite period. It may, however, be terminated by either of the Contracting State by giving a written notice of termination to the other Contracting State. The termination shall take effect after six months of the date of such notice.
3. Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of prisoners who have been transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Male the 12th day of November 2011, in the Hindi, English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation, the English text shall prevail.

Sd/-

Ranjan Mathai
Foreign Secretary

For the Government of
the Republic of India

Sd/-

Mohamed Naseer
Foreign Secretary

For the Government of
the Republic of Maldives

[F. No. 17011/8/2009-PR]

S. SURESH KUMAR, Jt. Secy.